



247

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मोप्र० ग्वालियर, मोप्र०

रा०अपी०प्र०क०

अप्र० ८७१-१-१५
ग्वालियर

अप्र० ८७१-१-१५

अवेदनगत

1. रामेश्वर पिता पन्ना लाल चौरसिया नि० मोहन्दा, तह०-सिमरिया, जिला-पन्ना मोप्र०।

2. भूषण पिता बृन्दावन चौरसिया नि० मोहन्दा तह०-सिमरिया, जिला-पन्ना मोप्र०

बनाम

1. श्री शालिगराम पिता श्री हल्के चौरसिया
2. श्री रामेश्वरी पिता श्री रामसेवक गुप्ता
3. श्री सुखदेव, पिता श्री रामसेवक गुप्ता
4. श्री दीपक गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
5. श्री केदारनाथ गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
6. श्री कृष्णकुमार गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
7. श्रीमति लक्ष्मी गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता
8. कु० पूनम गुप्ता पिता श्री रामसेवक गुप्ता

सभी नि० मोहन्दा तह०-सिमरिया, जिला-पन्ना मोप्र०

अवेदनगत

निम्नलिखी अंतर्गत धारा ५० मोप्र०भ०रा०सं० 1959

अपील विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् कमिशनर महोदय सागर संभाग सागर के अपी०प्र०क० 307/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

आवेदनगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर हितेश्वर प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं कि :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि उत्तरार्थी/आवेदक शालिगराम पिता हल्कू चौरसिया नि० मोहन्दा तह०-सिमरिया/पवई, के द्वारा मोप्र०भ०रा०सं० 1959 की धारा 250 के अंतर्गत ग्राम मोहन्दा की आ०न० 2452/१क, 2452/१ख/२ रकवा 0.006, 0.141 हैव० कुलकिता 2 कुल रकवा 0.147 हैव० आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक ने दिनांक 11-01-2013 को सीमांकन कराया था आ०न० 2452/१ख/२ रकवा 0.141 हैव० अंश रकवा 10×15 कड़ी पर अनावेदक द्वारा पान के डिल्ले रख कर जबरन कब्जा किया गया अनावेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 12-01-2013 को सीमांकन के पत्थर उखाड़ कर फैक दिये अतः

P
14

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रक्षा नं. दिनांक	प्रकरण क्रमांक निगरानी 871-एक / 2015 तथा कार्यवाही तथा आदेश	जिला -पन्ना	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
२०.१.१७	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 307/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13.4.15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोहन्द्रा तहसील पवई की आराजी नंबर 2452/1क, 2452/1ख/2 रकवा क्रमशः 0.006 एवं 0.141 हैक्टेयर कुल किता 2 रकवा 0.147 है0 की भूमि आवेदक शालिगराम (इस न्यायालय में अनावेदक) भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है जिसका सीमांकन कराकर संहिता की धारा 250 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी नंबर 2452/1ख/2 रकवा 0.141 है0 अंश रकवा 10x15 कड़ी पर अनावेदक (इस न्यायालय में आवेदक) द्वारा पान के डिब्बे रखकर जबरन कब्जाकिया गया है जिसे हटवाकर कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसील सिमरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक पंजीबद्ध कर रामेश्वर आदि को तलब किया गया। अनावेदकगण द्वारा अपने जबाब में बताया कि उनका कब्जा 1996 से लगातार चला आ रहा है जिस पर ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं की</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i></p>		

(Signature)

है। तहसीलदार सिमरिया द्वारा प्रकरण में अनावेदकगण का कब्जा पाते हुये कब्जा हटाने का आदेश दिनांक 29.3.14 को पारित किया जिससे परिवेदित होकर आवेदक रामेश्वर चौरसिया आदि ने अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा दिनांक 27.5.2014 को आदेश पारित रामेश्वर चौरसिया आदि की अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी पवई के आदेश दिनांक 27.5.2014 से दुखित होकर रामेश्वर चौरसिया द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की। आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.4.15 द्वारा आवेदक की अपील निराधार होने से निरस्त की गई जिससे से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि उपरोक्त आराजी नंबर आवेदक के स्वामित्व की भूमि है। अनावेदक ने दिनांक 11.1.13 को सीमांकन कराया था। आराजी नंबर 2452 / 1ख / 2 रकवा 0.141 है 0 अंश रकवा 10x15 कड़ी पर अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा कर पान के डिब्बे रख लिये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि दिनांक 12.1.13 को सीमांकन के दौरान लगाये गये पत्थर उखाड़ कर फेंक दिये गये हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि सीमांकन के दौरान आवेदकगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है और न ही सरहदी कृषकों को सूचना दी गई है, बिना वैधानिक प्रक्रिया

(M)

R
21/5/15

के सीमांकन किया गया है। आवेदक के भाई अशोक पिता पन्नालाल चौरसिया को दिनांक 3.11.96 को ग्राम पंचायत मोहन्द्रा द्वारा प्रस्ताव क्रमांक सी दिनांक 30.6.96 द्वारा अधिकार पत्र प्रदान किया गया था अधिकार पत्र में आराजी नंबर 2409 मोहन्द्रा की बस स्टैण्ड की आवादी भूमि 6x6 वर्ग फुट का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। अपने तर्क में यह भी कहा है कि रामेश्वरी गेंडा की भूमि के पश्चिम में अनावेदक शालिगराम की कोई भूमि नहीं है तथा आवादी भूमि सुरक्षित होने के पश्चात् आवादी के भू—खण्ड के वितरण का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है नक्शे में संदेहस्पद स्थिति के अनुसार नाप की गई है जो कुंआ को मानकर नाप किया गया है जबकि भूमि की नाप मूल चौहददी से होना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण का आज तर्क सन् 1996 से कब्जा चला आ रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा कभी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक—1 का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि उपरोक्त निर्णय पारित करने के पूर्व विवादित स्थल पर स्वयं जाकर स्थल निरीक्षण करना चाहिये था क्यों हिक जहां विवाद ऐसी भूमि से संबंधित हो जिसके चारों ओर मकान बने हैं तथा सामने शासकीय रास्ता लगा हुआ है और कोई भी कृषि भूमि नहीं है उसका भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिये तथा सरहददी भूमिस्वामी की नाप की सीमाएं जहां स्पष्ट अंकित न हो एवं स्थाई मुस्तकिल कोई सीमां चिन्ह नाप हेतु उपलब्ध न हो वहां पर

(M)

B
spu

अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं मौके पर जा कर स्थल निरीक्षण करना चाहिये था जो नहीं किया गया है क्यों कि बहर/कुआ को स्थई मुस्तकिल सीमा चिन्ह मान कर नाप करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण किये बगैर आदेश पारित करने में महान कानूनी भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि न्यायालय आयुक्त सागर द्वारा अनावेदकगण 2 लगायत 8 को प्रकरण में पक्षकार भी बनाया पक्षकार बनाये जाने के फलस्वरूप अपने आदेश को पारित करने में आदेश करते समय इन पक्षकारों की प्रकरण में क्या उपयोगिता थी इनका प्रकरण में क्या हित था, इनकी भी विवेचना न करते हुये दिनांक 13.4.15 को आदेश पारित करने में महान कानूनी भूल की है ऐसा आदेश अपने आप में निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे।

4- अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि ग्राम पंचायत को सरकारी भूमि के उपयोग की अनुमति की अनुज्ञाप्ति एक माह से अधिक के लिये प्रदान करने की अधिकारिता नहीं है। आवेदकगण न तो सरहदी कृषक हैं और न ही शासकीय भूमि पर कब्जेदार हैं। विचारण न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि खसरा नंबर 2492/1ख/2 रकवा 0.141 है 0 पर आवेदक रामेश्वर एवं भूषण

R
Ma

—5— प्रकरण क्रमांक निगरानी 871—एक / 2015

के पान के डिब्बे रखे हुये हैं अर्थात् अनाधिकृत कब्जा पाया गया। सीमांकन के समय आवेदकगण रामेश्वर आदि उपस्थित थे। अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी की भूमि पर डिब्बे रखकर अतिक्रमण होना पाये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 20.3.14 पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5— उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार सिमरिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 05/अ-70/2013-14 का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। जिसमें पाया गया कि विवादित भूमि स्थित ग्राम मोहन्द्रा की आराजी नंबर 2052/1ख/2 रकवा 0.141 है। शालिगराम पिता हल्के चौरसिया निवासी मोहन्द्रा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदकगण ने ग्राम पंचायत मोहन्द्रा द्वारा आराजी नंबर 2409 पर पान का डब्बा रखने हेतु अनुमति दिये जाने की छायाप्रति पेश की गई है किन्तु विवादित भूमि आराजी नंबर 2052/1ख/2 है। जिसका अनावेदक शालिगराम आदि द्वारा विधिवत् सीमांकन कराकर संहिता की धारा 250 केतहत विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि का सीमांकन पश्चात् कोई आपत्ति न आने से तहसीलदार

B
JK

सिमरिया ने राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार सिमरिया ने अनावेदक शालिगराम आदि द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के निराकरण हेतु चार वाद बिन्दु निर्धारित किया गया जिसको सिद्ध करने का भार आवेदक (इस न्यायालय में अनावेदक) के उपर होता है और अनावेदक शालिगराम आदि चारों वाद बिन्दु को सिद्ध करने में सफल रहा। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण रामेश्वर आदि को प्रतिपरीक्षण करने हेतु पूर्ण अवसर दिया गया तथा आवेदक द्वारा कथनों का भी प्रतिपरीक्षण भी किया गया। आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को विधिवत अपना पक्ष समर्थन रखने हेतु अवसर प्रदान किया जाकर विचारण न्यायालय आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है, इसलिये इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया। विवादित भूमि आबादी भूमि नहीं है वह खातेदार शालिगराम चौरसिया की स्वतंत्र खाते की भूमि है। वह आराजी नंबर 2452 का बटा नंबर है जो नक्शे में तरमीम है। आवेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि का पुनः सीमांकन नहीं कराया गया है, तहसीलदार सिमरिया के पत्र दिनांक 17.10.13 द्वारा मौका स्थल निरीक्षण हेतु गठित की गई, जिसके अनुसार राजस्व निरीक्षक पवई एवं 04 पटवारियों द्वारा दिनांक 23.1.13 को उभयपक्ष को विधिवत सूचना देकर स्थल निरीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर व सीमांकन प्रतिवेदन तथा स्थल

1/14

—7— प्रकरण क्रमांक निगरानी 871-एक/2015

निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदकगण का विवादित भूमि पर पश्चिम दिशा में पान का डब्बा रखकर बेजा कब्जा पाये जाने पर विधिवत संहिता में निहित प्रावधानों के तहत विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.03.2014 पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी तथा आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा की गई है। न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरुद्ध सत्यनारायण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि “ तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं ”

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सेमरिया का प्र०क्र० 5/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29.3.14 एवं अनुविभागीय अधिकारी पवई का प्र०क्र० 24/अप्रील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.5.14 तथा आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण क्रमांक 307/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13.04.15 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण स्थिर रखे जाते हैं। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(सूम० क०० सिंह)

सदुस्य

R
219